

प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी हेतु साप्ताहिक

शिक्षा सूत्र

www.shikshaSutra.com

शिक्षा सूत्र अखबार
घर पर मँगवाने
के लिए सम्पर्क करें
आनन्द शर्मा — 7665050402
कमल किशोर — 9982745862

वर्ष : 2, अंक : 27 उदयपुर, सोमवार, 02 मई 2016 पृष्ठ : 8, मूल्य : 5 रुपये

कॉलेज व्याख्याता भर्ती परीक्षा में भी शिक्षा सूत्र अखबार की रही धूम

24 अप्रैल, 2016 को आरपीएससी द्वारा कॉलेज व्याख्याता पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा के सामान्य अध्ययन के प्रश्न पत्र में समसामयिक ज्ञान और राजस्थान अध्ययन के कुल 100 प्रश्न शामिल थे। सामान्य अध्ययन के प्रश्न-पत्र के 100 प्रश्नों में से लगभग 40 प्रश्न शिक्षा सूत्र के अखबारों से आये हैं, ऐसा बहुत कम होता है जब कॉलेज व्याख्याता स्तर की परीक्षाओं में किसी एक

100 में से 40 प्रश्न शिक्षा सूत्र से

पुस्तक या गार्ड से इतने सारे प्रश्न आते हो। अगर आप शिक्षा सूत्र के नियमित पाठक हैं तो आप आसानी से इस प्रश्न-पत्र में सफलता हासिल कर सकते हैं। उक्त परीक्षा में शिक्षा सूत्र अखबार से आये प्रश्नों की सूची अखबार की अंक संख्या और पृष्ठ संख्या के साथ आगामी अंकों में प्रकाशित की जायेगी। इससे पूर्व महिला पर्यवेक्षक, वन रक्षक व वनपाल परीक्षाओं में भी शिक्षा सूत्र से प्रश्न आये थे।

नवीन भर्तियाँ

संघ लोक सेवा आयोग

पद नाम — भारतीय प्रशासनिक सेवा
पद संख्या — 1079
योग्यता — स्नातक
आयु सीमा — 21 से 32 वर्ष
अन्तिम तिथि — 27 मई 2016
Website : www.upsconline.nic.in
Direct Link : bit.ly/1Ty0CYT

राजस्थान लोक सेवा आयोग

पद नाम — राजस्थान प्रशासनिक सेवा
पद संख्या — राज्य सेवाएँ (334 पद), अधीनस्थ सेवाएँ (गैर टी.एस.पी क्षेत्र — 369 पद, टी.एस.पी क्षेत्र — 22 पद)
योग्यता — स्नातक
आयु सीमा — 21 से 35 वर्ष
आवेदन अवधि — 10 मई से 25 जून, 2016 तक
शुल्क जमा करवाने की अन्तिम तिथि — 23 जून, 2016
Website : rpsconline.rajasthan.gov.in
Direct Link : bit.ly/1WxnvOw

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पद नाम — प्रबन्धक एवं जूनि. कार्यकारी (फाइनेंस)
पद संख्या — 158
अन्तिम तिथि —
स्टेप-I ऑनलाईन पंजीकरण : 24 मई
स्टेप-II ऑनलाईन पंजीकरण : 01 जून
Direct Link - bit.ly/1SkfTJr

भारतीय थल सेना

पद नाम — हवलदार एज्यूकेशन
पद संख्या — 635
योग्यता — बीएससी/एमएससी/बीसीए/एमसीए/बीटेक/एमटेक/एमए/बीए
अन्तिम तिथि — 15 मई
Direct Link - bit.ly/1TaSeOB

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

पद नाम — जूनि. कार्यकारी (इलेक्ट्रिकल या सिविल इंजीनियरिंग, आईटी एवं एयरपोर्ट ऑपरेशन)
पद संख्या — 220
अन्तिम तिथि — 17 मई
Direct Link - bit.ly/1V8s7eJ

सरकारी योजना विशेषांक

पटवारी (मुख्य) परीक्षा, स्कूल व्याख्याता एवं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से केन्द्र सरकार और राजस्थान सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं का विवरण पृष्ठ 3, 4, 5, 7 और 8 पर दिया गया है।

BEFCI
An Institute of English Speaking & Personality Development
धारा प्रवाह अंग्रेजी सीखीये
ग्रामर के साथ • प्रभावशाली लेखन शैली बनाइए • मात्र 7 माह में 3 Months PD/PI Free Classes
9829832436 नये बैच प्रारम्भ (4 मई से)
9929552436 सुबह 7-9AM, सांय 4-6pm, 7-9pm
1 प्लोर, रिलायन्स फ्रेश के ऊपर, हिरण मगरी मैन रोड, सेक्टर-3, उदयपुर
IBPS(PO/CLERK) नये बैच प्रारम्भ
विशेष बैच — अंग्रेजी, गणित, तर्कशक्ति

8 वर्षों के लम्बे प्रयासों के बाद रियल एस्टेट अधिनियम 1 मई से प्रभावी होगा

30 अप्रैल, 2016। बहुप्रतीक्षित और व्यापक रूप से प्रशंसनीय रियल एस्टेट (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 1 मई, 2016 से प्रभावी हो जाएगा। इसके अंतर्गत विश्वास, विश्वसनीय लेनदेन और परियोजनाओं के कुशल और समयबद्ध निष्पादन के माहौल में रियल एस्टेट क्षेत्र के विकास को प्रोत्साहन देने और उपभोक्ताओं के हितों की सुरक्षा के लिए संस्थागत बुनियादी ढाँचे का सृजन और आवश्यक संचालन नियम बनाने की प्रक्रिया त्वरित गति से जारी है।

रेल मंत्री ने दो और यात्री अनुकूल सेवाओं की घोषणा की

29 अप्रैल, 2016। यात्री सुविधाओं से लेकर ढाँचागत विकास तक वित्त वर्ष 2016-17 की रेल बजट घोषणाओं को त्वरित गति से क्रियान्वित करने पर काम कर रहे रेल मंत्री श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु ने 29 अप्रैल, 2016 को रेल भवन में आयोजित एक कार्यक्रम में दो बहुत महत्वपूर्ण बजट घोषणाओं— (1) आईआरसीटीसी वेबसाइट एवं 139 (आईवीआरएस एवं एसएमएस) के जरिए पीआरएस काउंटर टिकटों का निरस्तीकरण (2) आईआरसीटीसी वेबसाइट के जरिए ई-टिकटिंग की अदायगी के लिए इंटरनेशनल डेबिट एवं क्रेडिट कार्डों की स्वीकृति, का उद्घाटन किया।

श्री एस.के. भगत रेलवे सुरक्षा बल के महानिदेशक नियुक्त

28 अप्रैल। कैबिनेट की नियुक्ति समिति ने सीआरपीएफ के विशेष महानिदेशक श्री एस.के. भगत, आईपीएस (उत्तराखंड — 82) की नियुक्ति महानिदेशक, रेलवे सुरक्षा बल, रेलवे बोर्ड के रूप में करने की मंजूरी दे दी है।

अहमदनगर का राहुरी बना देश का पहला डिजिटल लॉकर शुरु करने वाला नगर परिषद

28 अप्रैल, 2016। महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में स्थित राहुरी नगर परिषद डिजिटल लॉकर शुरु करने वाला देश का पहला नगर परिषद बन गया है। इस लॉकर के तहत सारे महत्वपूर्ण दस्तावेजों को डिजिटल रूप में ऑनलाइन स्टोर करके सुरक्षित रखा जा सकेगा। केंद्रीय दूरसंचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री श्री रवि शंकर प्रसाद ने डिजिटल इंडिया कार्यक्रम के हिस्से के तौर पर औपचारिक तौर पर इसका शुभारंभ किया।

राजस्थान के जैत्सर में 200 मेगावाट से अधिक क्षमता के सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के जैत्सर में केंद्रीय राज्य कृषि भूमि (सीएसएफ) की 400 हेक्टेयर की गैर कृषि योग्य भूमि पर 200 मेगावाट से अधिक क्षमता का सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की मंजूरी दे दी है। वर्तमान में यह भूमि राष्ट्रीय बीज निगम (एनएससी) के पास है, जो कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) है। सौर ऊर्जा संयंत्र सीपीएसई द्वारा लगाया जायेगा और उसका चयन बातचीत के जरिये किया जायेगा। एनएससी अपने अधिकार क्षेत्र से गैर कृषि योग्य भूमि निर्धारित सीपीएसई को उपलब्ध करायेगा। चयनित सीपीएसई सौर ऊर्जा संयंत्र स्थापित करने की लागत वहन करेगा।

ॐ चिंतामणि कोचिंग क्लासेज
हमारी ब्रांच अब टाउन हॉल पर भी
LBS के परिसर में
नया बैच प्रारम्भ, समय 9—1pm
2 दिन स्वयं के लिए निकाले, वास्तविक शिक्षण देखें
राजस्थान का एक मात्र संस्थान जिसका संचालन मानोविज्ञान विशेषज्ञ
शिक्षा शास्त्री एन.के. नागर द्वारा
स्थान :- LBS कोचिंग का परिसर, टाउन हॉल, उदयपुर
सम्पर्क : 0294-6050051, 9251050051, वाट्सएप : 9251050051

करंट अफेयर्स

राष्ट्रीय खबरें

- गुजरात की भाजपा सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े सवर्णों के लिए 10 फीसदी कोटा का ऐलान किया है। शुक्रवार, 29 अप्रैल को की गई इस घोषणा के मुताबिक छह लाख रुपए तक की वार्षिक आय वाले परिवारों को इसका लाभ मिलेगा।
- बॉलीवुड स्टार सलमान खान के बाद ओलंपिक स्वर्ण पदक विजेता भारतीय निशानेबाज अभिनव बिंद्रा ने भी रियो ओलंपिक में भारतीय दल के गुडविल एंबेसडर बनने का न्यौता स्वीकार किया।
- अल नीनो के बाद अब एशियाई देशों में ला नीनो का खतरा बढ़ गया है। मौसम विभाग ने इसकी वजह से कई क्षेत्रों में बाढ़ आने और भूस्खलन की आशंका जताई।
- पनामा पेपर्स में जिन लोगों के नाम आए हैं, उन सभी को सरकार ने नोटिस भेज दिया है। अरुण जेटली ने शुक्रवार, 29 अप्रैल को लोकसभा में यह जानकारी दी।
- दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी पाने वाले शीर्ष 100 सीईओ में तीन भारतीय मूल के हैं। इनमें से पेप्सीको की इंदिरा नूई, ल्योनडेलबेसल के भावेश पटेल और माइक्रोसॉफ्ट के सत्य नडेला शामिल हैं।
- मैडम तुसाद संग्रहालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला स्थापित किया गया है। इससे पहले भी कई भारतीय दिग्गजों के पुतले इस संग्रहालय में रखे जा चुके हैं।
- अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान (एम्स) में एक समारोह के दौरान पहली बार ऑटिज्म की बीमारी से पीड़ित एक बच्चे को विकलांगता प्रमाणपत्र दिया गया।
- श्रीहरिकोटा लॉन्चिंग सेंटर से नेविगेशनल सैटेलाइट IRNSS1G को प्रक्षेपित किया गया। इसके साथ ही भारत का अब अपना जीपीएस सिस्टम हो गया है। नेविगेशनल सैटेलाइट के सफल प्रक्षेपण पर पीएम मोदी ने कहा कि भारत को अपना नेविगेशनल सिस्टम मिल गया है, जिसे दुनिया नाविक के नाम से जानेगी।
- दिल्ली और मुंबई में अपना घर बनवाने के लिए अब आपको ऑनलाइन आवेदन करना होगा।
- राजस्थान के बाड़मेर में करीब 70 लाख टन के खनिज भंडार का पता चला है। भू-सर्वेक्षण विभाग की एक रिपोर्ट में बताया गया है कि इसमें हजारों वर्ष पुरानी चट्टानें हैं।
- काँग्रेस अध्यक्ष सोनिया गाँधी व उपाध्यक्ष राहुल गाँधी की उपस्थिति में कुलदीप विश्‍नोई ने अपनी हरियाणा जनहित काँग्रेस पार्टी का विलय काँग्रेस पार्टी में कर दिया।
- '9वें मॉस्को सैंड स्कल्चर चैंपियनशिप 2016' में भारत के मशहूर सैंड आर्टिस्ट सुदर्शन पटनायक ने गोल्ड मेडल जीता।
- संसदीय समिति ने विजय माल्या की राज्यसभा सदस्यता खत्म करने की सिफारिश की है। अगर माल्या की सदस्यता खत्म होती है तो वो ऐसे 15वें सांसद होंगे जिन्हें इस तरह सदन से निकाला जाएगा।
- बुंदेलखंड सहित महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सूखे के चलते पीने के पानी की भारी किल्लत को देख केंद्र जल्द ही पानी इस्तेमाल की नीति बनाने जा रहा है, जो देशभर में लागू होगी।
- राजमार्गों पर हरियाली के लिए केन्द्र सरकार 5000 हजार करोड़ रुपये खर्च करेगी। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा कि इस योजना को नरेगा से भी जोड़ा जाएगा।
- सीमा की रखवाली करने वाले विवाहित जवान अपने परिवार के साथ रह सकेंगे। इसके लिए बॉर्डर के

नजदीक गाँवों में उनके रहने के लिए नए आवास बनाए जाएंगे।

- राजमार्गों पर स्थित पुल की वजह से कोई दुर्घटना न हो, इसके लिए केंद्र सरकार ने कमर कस ली है। अब देशभर में पुल की निगरानी (इंस्पेक्शन) प्रशिक्षित ब्रिज इंस्पेक्टर करेंगे।
- बैंक ऑफ बड़ौदा की दिल्ली ब्रांच से विदेश में 6000 करोड़ रुपये भेजे जाने के मामले में एसआईटी द्वारा जाँच का आदेश दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को ये जिम्मेदारी सौंपी है।
- हरियाणा के छोटे से गाँव खंडा में जन्मे विनोद दहिया रियो ओलंपिक में आस्ट्रेलिया का प्रतिनिधित्व करेंगे। वह एक वर्ष पहले ही आस्ट्रेलिया के नागरिक बने हैं।
- महान् हस्तियों की तरह आप भी अपनी फोटो वाला डाक टिकट जारी करवा सकते हैं। डाक विभाग अपनी लोकप्रियता बढ़ाने के लिए गाजियाबाद में इस तरह की व्यवस्था जल्द ही शुरू करने जा रहा है।
- भारत-पाक विदेश सचिवों के बीच मंगलवार, 26 अप्रैल को नई दिल्ली में बातचीत हुई। पाक विदेश सचिव एजाज चौधरी हॉर्ट ऑफ एशिया कॉन्फ्रेंस में हिस्सा लेने भारत आये।
- मुख्यमंत्रियों और उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीशों के सम्मेलन में मोदी ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं का चुनाव एक साथ कराने की पुरजोर वकालत की।
- मनी लॉन्ड्रिंग के मामलों में आरोपियों के खिलाफ सख्त और त्वरित कार्रवाई के लिए माने जाने वाले कर्नल सिंह को वित्तीय सूचना ईकाई के निदेशक का अतिरिक्त पदभार सौंपा गया है।
- राजस्थान में हाल ही में किए गए वन्यजीव गणना के मुताबिक यहाँ पर ग्यारह तरह के वन्यजीवों में कमी देखी गई है जबकि आठ अन्य वन्यजीवों में बढ़ोत्तरी हुई है।
- अब किसानों को सिंगल विंडो सिस्टम के माध्यम से एक ही छत के नीचे तमाम सुविधाएँ मुहैया कराई जाएगी और उनकी समस्याओं का समाधान भी किया जाएगा।
- खाड़ी देशों के साथ आर्थिक संबंधों को एक नई दिशा देने के बाद केंद्र सरकार सामरिक संबंधों को और मजबूत बनाने की दिशा में काम कर रही है। सुन्नी बहुल अरब देशों और शिया बहुल ईरान के साथ संबंधों में बेहतर संतुलन साधने के नजरिए से तीन मई को भारतीय नौसेना की एक पूरी पलटन फारस की खाड़ी जाएगी।
- रेश ड्राइविंग को काबू करने के लिए सरकार 3डी वर्चुअल स्पीड ब्रेकर बनायेगी। केन्द्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने यह जानकारी दी।

अन्तर्राष्ट्रीय खबरें

- समुद्र में चीन की बढ़ती आक्रामकता पर चिंता के बीच भारत ने गुरुवार, 28 अप्रैल को नौवहन की आजादी का आह्वान किया। भारत ने कहा है कि समुद्री क्षेत्र तनाव और प्रतिद्वंद्विता से मुक्त होने चाहिए।
- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अमेरिकी संसद की संयुक्त सभा को 8 जून को संबोधित करने का न्यौता दिया गया है। मोदी अमेरिकी सीनेट को संबोधित करने वाले भारत के पाँचवें प्रधानमंत्री होंगे।
- भारतीय शिक्षाविद् राधा कुमार समेत 12 लोगों को यू.एन. यूनिवर्सिटी काउंसिल में नियुक्त किया गया।
- संयुक्त राष्ट्र ने बराक ओबामा और व्लादिमीर पुतिन से सीरिया शांति वार्ता को बचाने की अपील की है। संघर्ष विराम के बावजूद जारी हमले और राहत सामग्री

पहुँचाने में देरी से नाराज सीरियाई राष्ट्रपति बसर-अल असद के विरोधी गुट एक सप्ताह पहले ही वार्ता से अलग हो चुके हैं।

- साल 2020 तक अफ्रीका के छह देश मलेरिया मुक्त हो सकते हैं। डब्ल्यूएचओ की ओर से जारी एक रिपोर्ट में यह बात कही गई है।
- नासा की ओर से रोबोट की सेना शनि के बर्फीले चांद 'एन्सीलेडस' की सतह पर एलियन का पता लगाने जाएगी।
- सौर ऊर्जा से उड़ने वाला विमान सोलर इंपल्स-2 रविवार, 24 अप्रैल को कैलिफोर्निया में उतरा। इस विमान ने अब तक ओमान, भारत, म्यांमार और चीन को पार किया है।
- अमेरिका ईरान से 32 टन भारी जल खरीदेगा। परमाणु हथियारों के निर्माण में यह सबसे अहम घटक है जिसका उत्पादन यूएस खुद नहीं करता है।

आर्थिक खबरें

- विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड (एफआईपीबी) ने 13,000 करोड़ रुपये मूल्य के एफडीआई प्रस्तावों को मंजूरी दी है। जिसमें एक्सिस बैंक का 12,900 करोड़ रुपये का प्रस्ताव शामिल है।
- द्विपक्षीय संबंधों को मजबूती प्रदान करते हुए भारत ने शुक्रवार, 29 अप्रैल को पापुआ न्यू गिनी (पीएनजी) में 100 मिलियन डॉलर (करीब 664 करोड़ रुपये) के निवेश का प्रस्ताव रखा।
- देश में बीते 15 वर्षों के दौरान कॉरपोरेट टैक्स वसूली बढ़कर 12 गुनी हो चुकी है। आयकर से आने वाले राजस्व भी बढ़कर नौ गुने पर जा पहुँचा है। इसके बावजूद अर्थव्यवस्था में प्रत्यक्ष करों की हिस्सेदारी घटकर एक दशक के निचले स्तर 5.47 फीसदी पर आ गई है।
- हरियाणा सरकार बागवानी फसलों के विकास के लिए विजन 2026 पेश किया है। इसके तहत अगले दस साल बागवानी फसलों से किसानों की आय दस गुना बढ़ाने का लक्ष्य रखा गया है।
- ग्लोबल जीडीपी में भारत का हिस्सा दोगुना हो गया है। 2000 में यह हिस्सेदारी 1.43 फीसदी थी, जो 2015 में बढ़कर 2.86 फीसदी हो गई। शनिवार, 23 अप्रैल को उद्योग संगठन पीएचडी चैंबर ने यह बात कही।

खेल खबरें

- सुधा सिंह ने मैराथन के बाद 3000 मीटर स्टीपलचेज स्पर्धा में भी ओलंपिक के लिए क्वालीफाई किया।
- ग्रैंड स्लैम विम्बल्डन टेनिस टूर्नामेंट की पुरस्कार राशि में इस बार पाँच प्रतिशत की बढ़ोतरी की गई है। अब इसकी कुल राशि बढ़कर 2.81 करोड़ पाउंड हो गई है। विम्बल्डन का 130वाँ संस्करण 27 जून से 10 जुलाई के बीच आयोजित होगा।
- कश्मीर के बांदीपोर की रहने वाली सात साल की तजामुल इस्लाम विश्व किक बॉक्सिंग में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी।
- ब्राजील के रियो डि जेनेरियो में इस साल ओलंपिक खेलों (रियो 2016) का आयोजन होना है। परंपरा अनुसार इसकी मशाल अपना सफर ग्रीस के ऐतिहासिक स्थान ओलंपिया से शुरू करती है और ये 26 अप्रैल को मेजबान देश ब्राजील को सौंप दी गई।
- स्पेनिश खिलाड़ी राफेल नडाल ने बार्सिलोना ओपन टेनिस टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। यह नडाल के करियर का 49वाँ क्ले कोर्ट खिताब है।
- दत्तू बबन भोकानल ओलंपिक में खेलने वाले देश के नौवें नौकायन खिलाड़ी होंगे।

संपादकीय शिक्षा सूत्र

नजरिये का प्रभाव

अगर कोई काम करने की हमारी दिल से इच्छा हो तो वो काम करने के लिये हम प्रेरित होते हैं और जिस काम के लिये हम प्रेरित हुये है वो काम हम अच्छी तरह कर सकते हैं। प्रेरणा हम किसी से भी ले सकते हैं चाहे वो बड़ा हो या छोटा, मनुष्य हो या कोई प्राणी कोई भी हो सकता है, जैसे चींटी दीवार पर चढ़ती है और बार-बार गिरती है। लेकिन आखिर वह अपनी मंजिल तक पहुँच ही जाती है। वैसे ही छोटा बच्चा उठता है, गिरता है, फिर उठता है और फिर गिरता है। लेकिन वो जब तक उठकर खड़ा नहीं हो जाता तब तक अपना लक्ष्य नहीं छोड़ता है।

दोस्तों, हमारे जीवन में भी कई प्रेरणास्त्रोत है जिन्हें देखकर या उनके कार्यों को देखकर हमें प्रेरणा मिलती है। लेकिन हम प्रेरणा सकारात्मक लेते हैं या नकारात्मक लेते हैं, ये हमारे नजरिये पर निर्भर करता है। एक उदाहरण से हम इसे समझने की कोशिश करते हैं—

एक आदमी के दो बेटे थे। वे दोनों बड़े हुये तो उनमें से एक बड़ा बेटा व्यवसायी बना और दूसरा बेटा शराबी बना। एक दिन उस शराबी से उसके दोस्त ने पूछा की तुम ऐसे किस वजह से बने? तो उसने कहा कि बचपन से ही मैंने अपने पिताजी को शराब पीते देखा है, मैंने उनके गलत आदर्श देखें और मैं उनके जैसा बना हूँ।

उसी दोस्त ने दूसरे व्यवसायी बेटे से पूछा की तुम इतने बड़े बिजनेस मैन बने, उसका श्रेय किसको जाता है तो उसने कहा कि मेरे पिताजी को। मैंने बचपन से ही हर रोज पिताजी को शराब पीते हुये देखा। इन्सान को कैसा नहीं बनना है यह मैं रोज देखता और खुद को हमेशा कहता कि मुझे ऐसा नहीं बनना। एक ही व्यक्ति एक बेटे को सकारात्मक और दूसरे को नकारात्मक प्रेरणा दे सकता है। हमें कौनसी प्रेरणा लेनी है यह हम पर निर्भर करता है।

मॉडल पेपर अंक 26 की उत्तरमाला

1. (ब) 2. (ब) 3. (ब) 4. (स) 5. (द) 6. (स) 7. (द) 8.(स) 9. (स) 10. (ब) 11. (स) 12. (स) 13. (अ) 14. (अ) 15. (स) 16. (अ) 17. (स) 18. (द) 19. (अ) 20. (ब) 21.(स) 22. (द) 23. (अ) 24.(ब) 25.(अ) 26. (द) 27. (ब) 28. (स) 29. (ब) 30. (ब) 31.(द) 32.(स) 33.(अ) 34.(अ) 35.(ब) 36.(द) 37.(स) 38.(स) 39. (ब) 40. (अ) 41.(ब) 42.(अ) 43.(द) 44.(अ)

राजस्थान सरकार की योजनाएँ

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान

राजस्थान प्रदेश में जल की आवश्यकता एवं उपलब्धता में भारी अन्तर के दृष्टिगत राज्य सरकार ने 'मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान' के माध्यम से जल संकट के स्थायी समाधान को प्राथमिकता देने की अभिनव पहल की है। राज्य की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने 27 जनवरी, 2016 को झालावाड़ जिले के गर्दनखेड़ी गाँव से इस योजना का शुभारंभ किया। इसके साथ ही प्रदेश के 3,529 गाँवों में इस अभियान का आगाज भी हो गया।

दौड़ते पानी को चलना, चलते पानी को रेंगना, रेंगते पानी को रुकना सीखाने और रुके पानी को भूमि में समाहित करने के उद्देश्य से यह अभियान प्रारम्भ किया गया।

अभियान की कार्य अवधि 4 वर्ष रहेगी। प्रत्येक वर्ष की कार्य योजना में स्वीकृत कार्य उसी वर्ष 30 जून तक पूर्ण किये जाएँगे, प्रथम वर्ष में लगभग 3 हजार 529 गाँवों में जल संग्रहण एवं संरक्षण के कार्य किये जाएँगे। अगले तीन वर्ष में प्रतिवर्ष 6-6 हजार गाँवों को अभियान में शामिल किया जायेगा।

फोर वाटर संकल्पना (वर्षा जल, सतही जल, मृदा नमी और भू-जल) का उद्देश्य वर्षाकालीन जल का संरक्षण एवं अभिवृद्धि करते हुए जलग्रहण एवं सिंचित क्षेत्र विकास की व्यापक अवधारणा को साकार करना है।

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना

भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारम्भ 13 दिसम्बर, 2015 को राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य राजस्थान की सम्पूर्ण जनता को गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाना है। इस योजना का लाभ 'राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा योजना' एवं 'राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना' के अन्तर्गत आवरित परिवारों को मिलेगा। सामान्य बीमारियों हेतु प्रति परिवार 30,000 रुपये तक एवं जटिल बीमारियों हेतु प्रति परिवार 3,00,000 रुपये तक का इलाज सूचीबद्ध अस्पतालों में कैशलेस आधार पर भामाशाह कार्ड के जरिये करवाया जा सकता है। राजस्थान राज्य में करीब 1 करोड़ परिवार इस योजना से लाभान्वित होंगे।

न्यू इंडिया एश्योरेन्स को इस स्वास्थ्य बीमा योजना से वर्तमान वित्तीय वर्ष में करीब 180 करोड़ रुपये एवं आगामी वित्तीय वर्ष में 370 करोड़ रुपये का प्रीमियम प्राप्त होगा।

गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना

राजस्थान की मुख्यमंत्री श्रीमती वसुन्धरा राजे ने राज्य में बालिका संरक्षण के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वालों को सम्मानित एवं पुरस्कृत करने हेतु 'गरिमा बालिका संरक्षण एवं सम्मान योजना' लागू करने की घोषणा की। इस योजना के तहत प्रत्येक चयनित

व्यक्ति को 25 हजार रुपये की नकद राशि पुरस्कार के रूप में दी जाएगी।

मुख्यमंत्री राजश्री योजना

बालिका के जन्म के प्रति सकारात्मक सोच एवं उनके स्वास्थ्य तथा शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए 'शुभ लक्ष्मी योजना' के स्थान पर 'मुख्यमंत्री राजश्री योजना' लागू की गई। इस योजना के तहत 1 जून 2016 या उसके बाद जन्म लेने वाली बालिका के जन्म पर एवं उसकी प्रथम वर्षगांठ पर क्रमशः 2 हजार 500 रुपये एवं राजकीय विद्यालय में प्रथम कक्षा में प्रवेश लेने पर 4 हजार रुपये दिए जाएँगे।

योजनान्तर्गत लाभान्वित होने वाली बालिकाओं के शैक्षणिक स्तर में सुधार के लिए राजकीय विद्यालय में कक्षा 6 और 10 में प्रवेश करने पर क्रमशः 5 हजार रुपये एवं 11 हजार रुपये दिए जाएँगे। योजना के तहत राजकीय विद्यालय से 12वीं कक्षा उत्तीर्ण करने वाली बालिकाओं को 25 हजार रुपये दिए जाएँगे। इस योजना को भामाशाह योजना से जोड़ा जाएगा।

मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना

गत दो वर्षों में राज्य में 1 लाख 60 हजार से अधिक बालिकाओं को आत्मरक्षा प्रशिक्षण दिया गया है। इसकी लोकप्रियता को देखते हुए शिक्षा, गृह एवं महिला एवं बाल अधिकारिता विभागों के साथ समन्वय कर पूरे राज्य में आगामी 3 वर्ष में प्रतिवर्ष कक्षा 6 से 12 तक की 1 लाख 50 हजार बालिकाओं के लिए 'मुख्यमंत्री सक्षम बालिका योजना' चलाई जाएगी।

मुख्यमंत्री जन-सहभागिता विद्यालय विकास योजना

माध्यमिक शिक्षा के विद्यालयों में आधारभूत संरचना के निर्माण एवं विकास हेतु 'मुख्यमंत्री जन-सहभागिता विद्यालय विकास योजना' लागू की जायेगी, जिसमें 40 प्रतिशत राशि जनसहयोग से प्राप्त होने पर राज्य सरकार द्वारा 60 प्रतिशत राशि उपलब्ध करवायी जायेगी। आगामी वर्ष इस हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाना प्रस्तावित है।

मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना

शिक्षा विभाग के तत्वावधान में ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में उपलब्ध खेल मैदानों के विकास हेतु 'मुख्यमंत्री खेल मैदान विकास योजना' वर्ष 2016-17 में 2 हजार ऐसे खेल के मैदान विकसित किये जायेंगे जिन पर लगभग 150 करोड़ रुपये का व्यय होगा।

मुक्तिधाम विकास योजना

ग्रामीण क्षेत्रों में श्मशान एवं कब्रिस्तान में बुनियादी सुविधाओं के विकास के लिए 'मुक्तिधाम विकास योजना' के तहत वर्ष 2016-17 में 1 हजार से अधिक श्मशान-कब्रिस्तानों का विकास किया जायेगा।

सरकारी योजनाएँ

‘सेतु भारतम्’ योजना

शुरूआत — प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने महत्वाकांक्षी योजना 'सेतु भारतम्' का शुक्रवार, 4 मार्च 2016 को शुभारंभ किया।

उद्देश्य — पचास हजार करोड़ रुपए के निवेश से राष्ट्रीय राजमार्गों पर सुरक्षित और सुचारु यात्रा सुनिश्चित करने के लिए पुल निर्माण की महत्वाकांक्षी योजना है। इस योजना में 208 नए 'पुलों के ऊपर सड़क और पुलों के नीचे सड़कों का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही 1500 पुलों को चौड़ा, पुनः स्थापित और बदला जाएगा।

‘राजमार्ग परामर्श प्रणाली’ पायलट परियोजना

शुरूआत — केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग एवं नौवहन मंत्री श्री नितिन गडकरी ने गुरुवार, 10 मार्च 2016 को नई दिल्ली में दिल्ली-जयपुर राजमार्ग, एनएच-08 पर 'राजमार्ग परामर्श प्रणाली' की शुरूआत की।

उद्देश्य — एचएएस एक फ्री-टू-एयर जानकारी वितरण प्रणाली है जो राष्ट्रीय राजमार्ग पर यात्रा अनुभव को सुरक्षित, तेज और बाधा मुक्त बनाये जाने के लिए रेडियो में इस्तेमाल की जाती है।

‘उजाला’ में राष्ट्रीय एलईडी बल्ब योजना को नया रूप मिला

शुरूआत — 11 मार्च, 2016 को एलईडी आधारित घरेलू सक्षमता लाइटिंग कार्यक्रम (Domestic Efficient Lighting Programme.) को 'उजाला' नाम दिया गया। उजाला ऊर्जा सक्षमता सेवा लिमिटेड (ईईएसएल) द्वारा लागू 'सभी के लिए रियायती एलईडी से उन्नत ज्योति' (Unnat Jyoti by Affordable LEDs for All) कार्यक्रम का संक्षिप्त नाम है। इस योजना की शुरूआत 05 जनवरी, 2015 में हुई।

‘स्टैंड अप इंडिया’ योजना

शुरूआत — प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने नोएडा में मंगलवार, 05 अप्रैल, 2016 को 'स्टैंड अप इंडिया योजना' एवं 'स्टैंड अप इंडिया' के वेब पोर्टल की शुरूआत की।

उद्देश्य — इस योजना का उद्देश्य 10 लाख रुपये से लेकर 100 लाख रुपये तक के ऋण मुहैया कराकर अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और महिलाओं में उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है।

सामान्य अध्ययन (General Studies)

भारतीय इतिहास

सामाजिक एवं धार्मिक जागृति

अरविन्द घोष

- अरविन्द घोष बाल्यकाल से ही कुशाग्र बुद्धि वाले थे। इनका जन्म 15 अगस्त, 1872 को कलकत्ता के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुआ।
- ये अच्छे विद्वान, मानवतावादी, लेखक व दार्शनिक थे।
- उन्होंने ब्रिटिश सरकार द्वारा आयोजित आई.सी.एस. की परीक्षा उत्तीर्ण की।
- उनका राजनैतिक जीवन सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राष्ट्रीयता की दृष्टि से महत्वपूर्ण माना जाता है। वे गरम दल की विचारधारा के समर्थक थे। इसलिए वे ब्रिटिश सरकार की आँखों में खटकते थे।
- वे 1905 के बंग-भंग विरोधी आन्दोलन के प्रमुख नेताओं में से थे उन्होंने 'न्यू इण्डिया' और वन्देमातरम् का प्रकाशन कर बंगाल में राष्ट्रीय आन्दोलन को एक नई दिशा दी।
- 1910 में उन्होंने पाण्डिचेरी में आश्रय लिया, वहीं पर उन्होंने एक आश्रम की स्थापना की।
- धार्मिक दृष्टि से अरविन्द घोष एकेश्वरवाद के समर्थक थे। शक्ति की उपासना में विश्वास रखते थे।

बहाबी आन्दोलन

- धार्मिक और सामाजिक दृष्टि में भारत में मुस्लिम आन्दोलन की शुरुआत सैय्यद अहमद बरेलवी ने की।
- उनका आन्दोलन बाहबी आन्दोलन के नाम से जाना जाता है।
- इनके गुरु शाह वलीदउल्लाह (1704-63) ने प्रथम बार मुस्लिम समाज में व्याप्त कुरीतियों को समाप्त करने की वकालत की।

सर सैय्यद अहमद खाँ

- अलीगढ़ आन्दोलन के द्वारा सर सैय्यद अहमद खाँ (1817-98) ने भारतीय मुसलमानों को अंग्रेजी शिक्षा और आधुनिकीकरण की ओर प्रोत्साहित किया।
- उन्होंने मुसलमानों को रूढ़िवाद और अन्धविश्वास से मुक्त कर उनको सामाजिक सुधार और आधुनिक शिक्षा के लिए प्रेरित किया।
- प्रारम्भ में सर सैय्यद अहमद खाँ हिन्दू-मुस्लिम एकता के प्रबल समर्थक थे।
- मुसलमानों में शिक्षा के प्रसार की दृष्टि से उन्होंने 1864 में गाजीपुर में एक अंग्रेजी शिक्षा का स्कूल स्थापित किया।
- 1875 ई. में अलीगढ़ में 'ऐंग्लो ओरियन्टल' कॉलेज स्थापित किया जो आगे चलकर अलीगढ़ मुस्लिम विश्व विद्यालय के नाम से विख्यात हुआ।

अर्थव्यवस्था

जनसंख्या तथा नगरीकरण

- **सामाजिक केशिकात्व का सिद्धान्त** – इसके अनुसार आर्थिक विकास के साथ अधिक बच्चों की इच्छा में गिरावट होती है, प्रजनन दर में कमी होती है तथा साथ ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाओं में वृद्धि के कारण मृत्युदर में कमी होती है, जो प्रजनन दर में कमी की अपेक्षा अधिक तेज होती है।
- **जनसंख्या सिद्धान्तों तथा नीतियों से सम्बन्धित कुछ पारिभाषिक शब्द**
- **क्रुड या अशोधित जन्मदर** – किसी विशेष वर्ष में जन्में पंजीकृत कुल बच्चों की संख्या तथा उस वर्ष की कुल जनसंख्या के बीच अनुपात।
- **शोधित जन्म दर** – जब हम अशोधित जन्म दर में उन बच्चों के लिए जो पंजीकृत नहीं हैं, 5 प्रतिशत और जोड़ देते हैं, तो अशोधित जन्मदर शोधित जन्मदर हो जाती है।
- **क्रुड या अशोधित मृत्युदर** – किसी एक वर्ष में प्रति

1000 जनसंख्या पर मृतकों की संख्या को अशोधित मृत्युदर कहते हैं।

- **जनसंख्या की वृद्धि दर** – किसी एक वर्ष में अशोधित जन्मदर तथा मृत्युदर के अन्तर को जनसंख्या की वृद्धि दर कहते हैं।
- **शून्य जनसंख्या वृद्धि** – जन्मदर तथा मृत्युदर बराबर हो तो जनसंख्या की वृद्धि दर शून्य होगी।
- **मातृ मृत्युदर** – प्रति 1,00,000 जीवित जन्मों पर प्रसव के दौरान या गर्भ धारण होने के 42 दिनों के भीतर प्रसव के कारण मरने वाली माताओं (15 वर्ष से 49 वर्ष) की संख्या।
- **सामान्य प्रजनन दर** – किसी वर्ष में सजीव जन्में बच्चों की संख्या को सन्तानोत्पादक आयु वर्ग की स्त्रियों की संख्या से भाग देते हैं तो प्राप्त इन अनुपात को सामान्य प्रजनन दर कहते हैं।
- **शिशु मृत्युदर** – प्रति 1000 सजीव जन्में शिशुओं की संख्या के अनुपात में 1 वर्ष से कम आयु वाले मृत शिशु की संख्या।
- **बाल मृत्युदर** – किसी वर्ष में प्रति 1000 सजीव जन्में बच्चों की संख्या के सन्दर्भ में नवजात 0-4 वर्षों के बीच मृत बच्चों की संख्या।
- **सम्पूर्ण प्रजनन दर (TFR)** – बच्चों की वह संख्या जो किसी भी स्त्री के सम्पूर्ण प्रजनन काल (15-49 वर्ष) में पैदा हो।
- 2.1 कुल प्रजनन दर को जनसंख्या नीति के लक्ष्य के रूप में स्वीकार किया जाता है।
- **शिशु-स्त्री अनुपात** – प्रति हजार जन्म दे सकने वाली आयु की स्त्रियों पर 5 वर्ष से छोटे बच्चों की संख्या।

भूगोल

जलवायु

बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनें

- बंगाल की खाड़ी की मानसून पवनों की शाखा म्यांमार के तट तथा दक्षिण-पूर्वी बांग्लादेश के एक थोड़े से भाग से टकराती है।
- म्यांमार के तट पर स्थित अराकान पहाड़ियाँ इस शाखा के एक बड़े हिस्से को भारतीय उपमहाद्वीप की ओर विक्षेपित कर देती हैं।
- यह शाखा हिमालय पर्वत तथा भारत के उत्तर-पश्चिम में स्थित तापीय निम्नदाब के प्रभावाधीन दो भागों में बँट जाती है, इसकी एक शाखा गंगा के मैदान के साथ-साथ पश्चिम की ओर बढ़ती है और पंजाब के मैदान तक पहुँचती है। इसकी दूसरी शाखा उत्तर व उत्तर-पूर्व में ब्रह्मपुत्र घाटी में बढ़ती है।
- इसकी एक उपशाखा मेघालय में स्थित गारो और खासी की पहाड़ियों से टकराती है। खासी पहाड़ियों के शिखर पर स्थित मौसिनराम विश्व की सर्वाधिक औसत वार्षिक वर्षा प्राप्त करता है।

मानसून वर्षा की विशेषताएँ

- दक्षिण-पश्चिमी मानसून से प्राप्त होने वाली वर्षा मौसमी है, जो जून से सितंबर के दौरान होती है।
- मानसून वर्षा मुख्य रूप से भू-आकृति द्वारा नियंत्रित होती है।
- समुद्र से बढ़ती दूरी के साथ मानसून वर्षा में घटने की प्रवृत्ति पायी जाती है।
- किसी एक समय में मानसून वर्षा कुछ दिनों के आर्द्र दौरों में आती है। इन गीले दौरों में कुछ सूखे अंतराल भी आते हैं, जिन्हें विभंग या विच्छेद कहा जाता है।
- ग्रीष्मकालीन वर्षा मूसलाधार होती है, जिससे बहुत-सा पानी बह जाता है और मिट्टी का अपरदन होता है।
- भारत की कृषि-प्रधान अर्थव्यवस्था में मानसून का अत्यधिक महत्व है।
- मानसून वर्षा का स्थानिक वितरण भी असमान है, जो 12 से.मी. से 250 से.मी. से अधिक वर्षा के रूप में पाया जाता है।

पटवारी (मुख्य) परीक्षा, स्कूल व्याख्याता एवं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण

राजस्थान सरकार की योजनाएँ

मामाशाह योजना

मुख्यमंत्री वसुन्धरा राजे ने उदयपुर शहर से देश में महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी **मामाशाह योजना 2014** का 15 अगस्त, 2014 को शुभारम्भ किया। जो लैंगिक समानता, वित्तीय समावेशन एवं परिवार आधारित लाभों को सम्मिलित करते हुए विस्तृत कवरेज के साथ लागू हुई।

• **‘वाहन’ सॉफ्टवेयर** – इस सॉफ्टवेयर के माध्यम से वाहन पंजीयन का कार्य सभी परिवहन कार्यालयों में प्रारम्भ कर दिया गया।

• **‘सारथी’ सॉफ्टवेयर** – इस सॉफ्टवेयर योजना के माध्यम से लाइसेंस जारी करने का कार्य सभी परिवहन कार्यालयों में प्रारम्भ कर दिया गया।

ESCO MODEL योजना

मुख्यमंत्री द्वारा 04 मई, 2015 को घरेलु लाइटिंग में बिजली बचत हेतु एलईडी के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना प्रारम्भ की गई है।

मुख्यमंत्री जन आवास योजना-2015

प्रधानमंत्री आवास योजना व वर्ष 2022 तक सबको आवास उपलब्ध कराये जाने के लक्ष्य के मद्देनजर इस योजना का मुख्यमंत्री द्वारा 26 सितम्बर, 2015 को शुभारम्भ किया गया।

भूमि आवंटन नीति-2015

आम जनता व सामाजिक संस्थाओं के हितों को ध्यान में रखते हुए “राजस्थान के नगरीय क्षेत्रों में विभिन्न उद्देश्यों के लिए **भूमि आवंटन नीति**” का मुख्यमंत्री द्वारा 26 सितम्बर, 2015 को शुभारम्भ किया गया।

नन्द घर योजना

शुरुआत – नन्द घर योजना (Adopt an AWC) का औपचारिक शुभारम्भ 11 मई, 2015 को पाली जिले से किया गया।

उद्देश्य – आई.सी.डी.एस द्वारा दी जाने वाली सेवाओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए अग्रणी समाजसेवियों, दानदाता, स्वयंसेवी संगठन व कॉरपोरेट की सामाजिक दायित्व में भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए **नन्द घर योजना** आरम्भ की गई। इस योजना के अन्तर्गत आँगनवाड़ी केन्द्रों को गोद लिया जाता है।

अन्नपूर्णा भण्डार योजना

मुख्यमंत्री द्वारा 31 अक्टूबर, 2015 को जयपुर जिले के गाँव भम्पौरी में राज्य के पहले अन्नपूर्णा भण्डार को प्रारम्भ किया गया। सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अन्तर्गत सार्वजनिक-निजी सहभागिता के माध्यम से जनसाधारण को उचित मूल्य दूकानों पर उच्च गुणवत्ता की मल्टीब्राण्ड वस्तुएँ उचित दर पर उपलब्ध करवाने हेतु यह योजना आरम्भ की गई है।

माता यशोदा पुरस्कार योजना

इस योजना के अन्तर्गत राज्य की प्रत्येक बाल विकास परियोजना में एक सर्वश्रेष्ठ आँगनवाड़ी की कार्यकर्ता, सहायिका व आशा सहयोगिनी को पुरस्कृत किया जाता है। आँगनवाड़ी कार्यकर्ता की पुरस्कार राशि 5,100 रुपये, आँगनवाड़ी सहायिका व आशा सहयोगिनी की पुरस्कार राशि 2,100 रुपये है।

‘उत्सव भोज’ योजना

मिड-डे मील योजना के अन्तर्गत गुजरात राज्य की **‘तिथि भोजन’** जैसी जनसहयोग वाली योजना को राजस्थान प्रदेश में **‘उत्सव भोज’** के नाम से 02 सितम्बर, 2015 को शुरू किया गया।

पटवारी (मुख्य) परीक्षा, स्कूल व्याख्याता एवं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण

सरकारी योजनाएँ

ग्राम उदय से भारत उदय अभियान

शुरुआत — प्रधानमंत्री ने महू, मध्यप्रदेश में आयोजित एक सार्वजनिक सभा में 14 अप्रैल, 2016 को इस अभियान का शुभारंभ किया। यह अभियान 14 अप्रैल को डॉ. भीमराव अम्बेडकर की 125वीं जयंती पर शुरू हुआ और 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस पर सम्पन्न हुआ।

उद्देश्य — गाँवों में सामाजिक सौहार्द को बढ़ावा देना, पंचायती राज का मजबूतीकरण, ग्रामीण विकास को प्रोत्साहित करने के साथ-साथ किसानों की प्रगति को बढ़ावा देना है।

राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 'ई-नाम' प्रायोगिक परियोजना

शुरुआत — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किसानों को उनकी उपज का उपयुक्त मूल्य दिलाने के उद्देश्य से 14 अप्रैल, 2016 को राष्ट्रीय कृषि बाजार के लिए ई-ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म 'ई-नाम' (e-National Agriculture Market-NAM) की प्रायोगिक परियोजना की शुरुआत की। इसे ई-मंडी भी कहा गया है। इससे न केवल किसानों को फायदा होगा, बल्कि थोक कारोबार और उपभोक्ताओं को भी इसका लाभ मिलेगा। ई-मंडी प्लेटफॉर्म पर देशभर के किसी भी कोने के थोक कारोबारी गुणवत्तापूर्ण माल खरीद सकेंगे। खरीद-बिक्री में बिचौलियों का हस्तक्षेप खत्म होने से उपभोक्ताओं को कृषि उत्पाद वाजिब दाम पर मिलने का रास्ता साफ होगा।

उद्देश्य — इसका उद्देश्य देशभर में कीमतों में होने वाले अंतर को खत्म करना है। इससे जमाखोरी की प्रवृत्ति पर रोक लगेगी, जिससे अंततः खाद्य महंगाई में कमी आएगी। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए पुराने कानून में संशोधन करना होगा। अभी इस पुराने कानून के तहत ही मंडियों में कृषि उपजों की खरीद और बिक्री होती है। इस कानून को कृषि उपज विपणन अधिनियम (Agricultural Produce Market Act) कहा जाता है।

राजीव गांधी खेल अभियान योजना का नाम बदल कर 'खेलो इंडिया' किया

नाम — केंद्र सरकार ने राजीव गाँधी खेल अभियान योजना का नाम बदल कर 'खेलो इंडिया' कर दिया है। **उद्देश्य** — इस फैसले का उद्देश्य देश में प्रतिस्पर्धात्मक माहौल पैदा करना है। सरकार की मंशा खेल को और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने की है और 'खेलो इंडिया' नाम से प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होती है। यही वजह है कि पुराने नाम को बदलकर नया नाम दिया गया है। **शुरुआत** — राजीव गाँधी खेल अभियान योजना को पिछली यूपीए सरकार ने फरवरी, 2014 में 'पंचायत युवा क्रीड़ा और खेल अभियान' की जगह शुरू किया था। इसके अलावा पिछली सरकार के कार्यकाल में शुरू की गई दो अन्य खेल परियोजनाओं 'शहरी खेल आधारभूत ढांचा योजना' और 'राष्ट्रीय खेल प्रतिभा खोज योजना' का भी 'खेलो इंडिया' में विलय कर दिया गया है।

राष्ट्रीय एलईडी बल्ब योजना

शुरुआत — 05 जनवरी, 2015।

उद्देश्य — घरेलू बिजली बचत और घरों तथा सड़कों पर एलईडी बल्ब लगाए जाने संबंधी राष्ट्रीय योजना है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

शुरुआत — 13 जनवरी, 2016 को भारत सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना नामक एक नई फसल

बीमा पॉलिसी शुरू की है। यह दो योजनाओं राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (NATIONAL AGRICULTURAL INSURANCE SCHEME) और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना (Revised NATIONAL AGRICULTURAL INSURANCE SCHEME) की जगह लेगी। बीमा योजना को एक मात्र बीमा कंपनी, भारतीय कृषि बीमा कंपनी (एआईसी) द्वारा नियंत्रित किया जाएगा। 2016-2017 के बजट में प्रस्तुत योजना का आवंटन 5,550 करोड़ रुपये का है।

उद्देश्य — • प्राकृतिक आपदाओं, कीट और रोगों के परिणामस्वरूप अधिसूचित फसल में से किसी की विफलता की स्थिति में किसानों को बीमा कवरेज और वित्तीय सहायता प्रदान करना। • कृषि में किसानों की सतत् प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए उनकी आय को स्थायित्व देना। • किसानों को कृषि में नवाचार एवं आधुनिक पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित करना। • कृषि क्षेत्र में ऋण के प्रवाह को सुनिश्चित करना।

बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ योजना

शुरुआत — प्रधानमंत्री ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना की शुरुआत की।

उद्देश्य — इसका उद्देश्य कन्याभ्रूण हत्या को रोकने के साथ-साथ बेटियों की सुरक्षा करना है।

'सुकन्या समृद्धि खाता' योजना

शुरुआत — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 22 जनवरी, 2015 को हरियाणा के पानीपत में 'सुकन्या समृद्धि योजना' की शुरुआत की।

उद्देश्य — जिसके तहत लड़की के माता-पिता बेटी के नाम से उसके 10 वर्ष से कम उम्र में ही बैंक में खाता खुलवा सकेंगे। सुकन्या समृद्धि खाते में 14 वर्षों तक रुपये जमा किये जा सकते हैं एवं इस खाते को चालू रखने की अवधि 21 वर्ष अथवा कन्या के विवाह तक तय की गई है। सुकन्या समृद्धि योजना का लक्ष्य लड़कियों को सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराना है।

एनयूएलएम का नाम अब दीन दयाल अंत्योदय योजना-एनयूएलएम

नाम — सरकार द्वारा 'राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' (एनयूएलएम) का नया नाम 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-एनयूएलएम' कर दिया गया। इसका हिंदी में नाम 'दीनदयाल अंत्योदय योजना-राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन' है।

उद्देश्य — कौशल विकास एवं प्रशिक्षण, निजी और सामूहिक सूक्ष्म उद्योग, स्वयं सहायता समूहों के गठन, बेघरों के लिए आश्रयों के निर्माण, बुनियादी ढाँचे के निर्माण के लिए सड़क पर सामान बेचने वालों, विकलांगों तथा कूड़ा बीनने वालों की मदद के नये तरीके से यह मिशन शहरों में रहने वाले गरीबों के लिए रोजगार के अवसर और आय बढ़ाने के उपाय खोजता है। एनयूएलएम की शुरुआत पिछली यूपीए सरकार के समय वर्ष 2013 में की गई थी।

श्यामा प्रसाद मुखर्जी रूबन मिशन

शुरुआत — प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 21 फरवरी, 2016 को छत्तीसगढ़ के राजनंदगाँव जिले के कुरुमात नामक स्थान से राष्ट्रीय रूबन मिशन का शुभारंभ किया। रूबन मिशन पिछली सरकार के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाएँ प्रदान करने के कार्यक्रम (Providing Urban Amenities to Rural Areas ,PURA) से संबंधित प्रावधानों का स्थान लेगा।

उद्देश्य — रूबन मिशन 'ग्रामीण आत्मा और शहरी

सुविधाओं' से युक्त कलस्टर आधारित विकास करने में सक्षम होगा। योजना स्मार्ट गाँवों का निर्माण करके स्मार्ट शहरों की पहल की पूरक बनेगी। उन्होंने रूबन कलस्टरों को आर्थिक गतिविधियों का केंद्र बताया जो विकास को प्रोत्साहित करेंगे और आसपास के गाँव में जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाएँगे। योजना के माध्यम से जहाँ एक ओर ग्रामीण विकास को सशक्त किया जायेगा वहीं दूसरी ओर शहरी क्षेत्रों से अतिरिक्त दबाव को कम किया जा सकेगा।

नई मंजिल योजना

शुरुआत — केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. नजमा हेपतुल्ला ने नई केंद्रीय क्षेत्र योजना — नई मंजिल का पटना में 8 अगस्त, 2015 को शुभारंभ किया। नई मंजिल योजना सामान्य रूप से अल्पसंख्यक समुदायों, विशेष रूप से मुसलमानों की शैक्षिक और जीविकोपार्जन की जरूरतों में सहायता प्रदान करेगी, क्योंकि मुसलमान शैक्षिक योग्यताओं में अन्य अल्पसंख्यक समुदायों से पीछे हैं। यह योजना स्कूल से बाहर आए या बीच में ही पढ़ाई छोड़ चुके सभी छात्रों और मदरसों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए एक नई दिशा और एक नया लक्ष्य प्रदान करती है।

उद्देश्य — इस योजना का उद्देश्य प्रशिक्षकों को ब्रिज पाठ्यक्रमों के द्वारा शैक्षिक भागीदारी उपलब्ध कराना है ताकि उन्हें दूरस्थ शिक्षा के माध्यम से 12वीं और 10वीं कक्षा के प्रमाणपत्र उपलब्ध हो सकें। इसी के साथ-साथ उन्हें चार पाठ्यक्रमों विनिर्माण, इंजीनियरिंग, सेवाएँ और सरल कौशल में ट्रेड आधार पर कौशल प्रशिक्षण भी उपलब्ध कराना है।

LICAAO EXAM 2016

शिक्षा सूत्र अखबार और सामान्य अध्ययन प्रश्नोत्तरी से LICAAO परीक्षा में आये प्रश्न

पिछले अंक का शेष

32. चाबहार बंदरगाह किस देश में स्थित है — ईरान।
33. पद्म भूषण गिरिजा देवी का सम्बन्ध किस से है — बनारस घराने के शास्त्रीय गायन से।
34. ललितपुर थर्मल पावर प्लान्ट किस राज्य में स्थित है — उत्तर प्रदेश।
35. ब्रह्मपुत्र क्रेकर एण्ड पॉलिमर लि. कहाँ स्थित है — असम।
36. इको मार्क का चिन्ह क्या है — मिट्टी का बर्तन।
37. बजरंग पुनिया कौन है — भारतीय पहलवान।
38. कोसी बेसिन विकास परियोजना का सम्बन्ध किस राज्य से है — बिहार।
39. व्यष्टिपरक विश्लेषण को क्या कहते हैं — कीमत सिद्धान्त।
40. दमिश्क किस देश की राजधानी है — सीरिया।
41. वर्ष 2016 की एशियन कुश्ती चैम्पियनशिप कहाँ आयोजित हुई — बैंकाक (थाईलैण्ड)।
42. वर्ष 2016 के बर्लिन फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ बाल फिल्म का अवार्ड किसे प्राप्त हुआ — ऑट्टल।
43. एशियन इनडोर एथलेटिक्स चैम्पियनशिप, 2016 कहाँ आयोजित हुई — दोहा, कतर।
44. बलराम जाखड़ का सम्बन्ध किस से है — काँग्रेस नेता (निधन — फरवरी, 2016)।
45. स्वामी विवेकानन्दजी किस धार्मिक सम्मेलन से प्रसिद्ध हुए — शिकागो।
46. बुक्सा नेशनल पार्क कहाँ स्थित है — पश्चिम बंगाल (भारत)।

सामान्य अध्ययन मॉडल पेपर-27

भारतीय राज व्यवस्था

1. भारतीय संविधान द्वारा अवशेष शक्तियाँ दी गई हैं—
अ.) केन्द्र को ब.) राज्यों को
स.) दोनों को द.) सर्वोच्च न्यायालय और न्यायपालिका को
2. समवर्ती सूची में किसी विषय पर संसद तथा किसी राज्य के विधानमण्डल द्वारा परस्पर विरोधी कानून बना दिये जाने की स्थिति में
अ.) संसद का कानून मान्य होगा
ब.) राज्य में राज्य विधानमण्डल का कानून मान्य होगा
स.) दोनों का कानून मान्य होगा
द.) किसी का भी कानून मान्य नहीं होगा
3. भारतीय संघ के राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने की व्यवस्था संविधान के अनुच्छेद में की गई है—
अ.) अनुच्छेद-352 ब.) अनुच्छेद-354
स.) अनुच्छेद-372 द.) अनुच्छेद-360
4. 'जम्मू-कश्मीर राज्य को विशेष स्थिति' संविधान के किस अनुच्छेद के आधार पर प्रदान की गई है
अ.) अनुच्छेद-368 ब.) अनुच्छेद-370
स.) अनुच्छेद-372 द.) अनुच्छेद-374
5. अनुच्छेद-352 के अन्तर्गत जारी की गई आपातकालीन घोषणा कितने समय तक जारी रहती है यदि संसद के दोनों सदन उसे स्वीकृति प्रदान न करें—
अ.) 3 महीने ब.) 4 महीने
स.) 1 महीने द.) 6 महीने
6. युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह सम्बन्धी आपातकालीन घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अन्तर्गत की जा सकती है?
अ.) अनुच्छेद-360 ब.) अनुच्छेद-352
स.) अनुच्छेद-356 द.) अनुच्छेद-358
7. आपातकालीन प्रावधानों का उल्लेख संविधान के किस भाग में किया गया है?
अ.) भाग-18 ब.) भाग-16
स.) भाग-14 द.) भाग-20
8. संविधान के अनुच्छेद-352 के अन्तर्गत अब तक आपातकाल कितनी बार घोषित किया गया है?
अ.) 2 बार ब.) 3 बार
स.) 4 बार द.) 5 बार
9. राज्य की मन्त्रिपरिषद् को अपना त्यागपत्र देना होता है—
अ.) जब राष्ट्रपति ऐसा चाहे
ब.) जब राज्यपाल ऐसा चाहे
स.) जब विधानसभा अविश्वास का प्रस्ताव पास कर दे
द.) जब राज्य की विधानपरिषद् अविश्वास का प्रस्ताव पास करें
10. संघ में राज्यसभा द्वारा और राज्य में विधानपरिषद् द्वारा वित्त विधेयक को अधिक से अधिक रोका जा सकता है—
अ.) 21 दिन ब.) 14 दिन
स.) 2 माह द.) 4 माह

कम्प्यूटर

11. भाषा, जिसे कम्प्यूटर समझता है व निष्पादित करता है, कहलाती है।
अ.) अमेरिकन भाषा
ब.) मशीनी भाषा
स.) गुप्त प्रच्छल भाषा
द.) इन्टीग्रल बिजनेस मशीन
12. आई.बी.एम. का पूर्ण रूप है—
अ.) इण्डियन बिजनेस मशीन
ब.) इन्टरनेशनल बिजनेस मशीन
स.) इटैलियन बिजनेस मशीन

- द.) इन्टीग्रल बिजनेस मशीन
13. कम्प्यूटर में 'पासवर्ड' सुरक्षा करता है—
अ.) हार्डवेयर के पुराने पड़ने से
ब.) सॉफ्टवेयर की त्रुटियों से
स.) तंत्र के अनाधिकृत अभिगमन से
द.) उपर्युक्त में से कोई नहीं
14. इलेक्ट्रॉनिक कम्प्यूटर का आविष्कार किसने किया?
अ.) मोचले एवं एकर्ट
ब.) कॉर्ल बेन्ज
स.) थॉमस अल्वा एडीसन
द.) एडवर्ड टेलर
15. भारत में सुपर कम्प्यूटर 'परम' का निर्माण किया गया।
अ.) चेन्नई में ब.) बंगलौर में
स.) दिल्ली में द.) पूणे में
16. 'लीनेक्स' एक क्या है?
अ.) ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम
ब.) एक बीमारी का नाम
स.) एक केमिकल का नाम
द.) एक कम्प्यूटर वायरस
17. I.C का अर्थ क्या होता है?
अ.) अन्तः संयोजित
ब.) इन्टीग्रेटेड सर्किट (संघटित परिपथ)
स.) अपूर्ण परिपथ
द.) उपर्युक्त में से नहीं
18. सी.डी. रोम का पूर्ण रूप है—
अ.) कोर डिस्क रीड ऑनली मैमोरी
ब.) कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ऑनली मैमोरी
स.) सरक्यूलर डिस्क रीड ऑनली मैमोरी
द.) उपर्युक्त में से कोई नहीं
19. कम्प्यूटर का जनक किसे समझा जाता है—
अ.) चार्ल्स बेबेज ब.) हॉलरिथ
स.) लेबनिज द.) ब्लेज पास्कल
20. एक सिस्टम, जिसमें दो अवस्थाएँ रहती हैं, उसे कहते हैं?
अ.) ऑपरेटिंग सिस्टम ब.) द्विवर्गीय सिस्टम
स.) बाइनरी सिस्टम द.) कम्प्यूटर सिस्टम

सामान्य विज्ञान

21. कोशिका द्रव्य में संरचना विहिन तरल पदार्थ कहलाता है—
अ.) जीवद्रव्य ब.) ट्रॉफोप्लाज्म
स.) हायलोप्लाज्म द.) मेटाप्लास्ट
22. निम्न में से कौनसा कोशिका अंगक दोहरी झिल्ली से घिरा रहता है?
अ.) राइबोसोम ब.) तारक काय
स.) माइटोकॉन्ड्रिया द.) लाइसोसोम
23. किस कोशिकांग को कोशिका की 'आत्मघाती थैलिया' कहा जाता है?
अ.) केन्द्रक ब.) माइटोकॉन्ड्रिया
स.) राइबोसोम द.) लाइसोसोम
24. प्रोकेरियोटिक कोशिका का उदाहरण है—
अ.) नीले-हरे शैवाल ब.) कवक
स.) पादप द.) जन्तु
25. प्रारूपी पादप कोशिकाओं के केन्द्रक की सामान्यतया स्थिति होती है—
अ.) केन्द्रकीय ब.) परिधीय
स.) आधारी द.) किसी भी भाग में
26. माइटोकॉन्ड्रिया की आन्तरिक झिल्ली की अतिवृद्धियों पर स्थित असंख्य सूक्ष्म संतृन्त कण कहलाते हैं—
अ.) ऑक्सीसोम ब.) क्रिस्टी

- स.) मैट्रिक्स द.) तारक केन्द्र
27. निम्न में से किस कोशिकांग में डी.एन.ए पाया जाता है—
अ.) अन्तःप्रद्रव्यी जालिका ब.) माइटोकॉन्ड्रिया
स.) लाइसोसोम द.) गॉल्जी काय
28. कोशिका का शक्ति गृह कहलाता है—
अ.) माइटोकॉन्ड्रिया ब.) केन्द्रक
स.) केन्द्रिका द.) लवक
29. कौनसे कोशिकांग को बिल्ली तथा उल्लू की तन्त्रिका कोशिकाओं में खोजा गया—
अ.) राइबोसोम ब.) माइटोकॉन्ड्रिया
स.) तारक काय द.) गॉल्जी काय
30. पादपों के किस कोशिका अंगक में प्रकाश की उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट्स का संश्लेषण होता है—
अ.) हरित लवक ब.) केन्द्रक
स.) अन्तःप्रद्रव्यी जालिका द.) माइटोकॉन्ड्रिया

राजस्थान अध्ययन

31. कुमलगढ़ दुर्ग है—
अ.) गिरी दुर्ग ब.) धान्वन दुर्ग
स.) जल दुर्ग द.) वन दुर्ग
32. स्वामी भक्त पन्नाधाय की कथा किससे जुड़ी है?
अ.) अचलगढ़ ब.) रणथम्भौर
स.) मांडलगढ़ दुर्ग द.) कुंभलगढ़
33. गौरा-बादल महल व नवलखा बुर्ज स्थित है।
अ.) चित्तौड़गढ़ दुर्ग ब.) कुंभलगढ़ दुर्ग
स.) रणथम्भौर दुर्ग द.) जालोर दुर्ग
34. एक घर में एक साथ छह चूल्हे किस पुरातात्विक स्थल में प्राप्त हुए हैं?
अ.) कालीबंगा ब.) आहड़
स.) गिलुण्ड द.) बागोर
37. किस सभ्यता का संबंध ईरान से माना जाता है?
अ.) बालाथल ब.) रंगमहल
स.) आहड़ द.) बागोर
38. हेनसांन निम्न में से किस पुरातात्विक स्थल पर आया था?
अ.) बैराठ ब.) नगरी
स.) नलियासर द.) नगर
39. शंख लिपि के प्रचुर संख्या में प्रमाण उपलब्ध हुए हैं—
अ.) बैराठ ब.) नोह
स.) गणेश्वर द.) बागोर
40. अशोक कालीन गोल बौद्ध मंदिर व स्तूप प्राप्त हुए हैं—
अ.) बीजक की पहाड़ी ब.) भीमजी की पहाड़ी
स.) महादेव जी की ढूंगरी द.) हनुमान जी की ढूंगरी
41. शिवि जनपद के सिक्के प्राप्त हुए हैं—
अ.) जोधपुर ब.) नगरी
स.) नगर द.) तिलवाड़ा
42. नलियासर कौनसे जिले में स्थित है?
अ.) जयपुर ब.) टोंक
स.) बाड़मेर द.) झुंझुनू
43. चौहान युग से पूर्व की सभ्यता का ज्ञान किस पुरातात्विक स्थल से प्राप्त होता है?
अ.) नलियासर ब.) नगर
स.) बैराठ द.) बागोर

नोट : इस मॉडल पेपर की उत्तरमाला अगले अंक में पेज 3 पर दी जायेगी।

त्रुटि सुधार :- अंक 23 और 25 में प्रकाशित कम्प्यूटर के प्रश्नों की उत्तरमाला गलत मुद्रित होने पर खेद है। सही उत्तर नीचे दीये गये हैं—
अंक 23 :- 11.) अ, 12.) स, 20.) स
अंक 25 :- 2.) द, 4.) द, 6.) स, 10.) स

शिक्षा सूत्र के पुराने अख़बार खरीदने के लिए सम्पर्क करें – 7665050402

पटवारी (मुख्य) परीक्षा, स्कूल व्याख्याता एवं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्त्वपूर्ण

सरकारी योजनाएँ

जम्मू-कश्मीर में 'नई मंजिल' योजना

शुरूआत — जम्मू-कश्मीर में पहली बार 20 जनवरी, 2016 'नई मंजिल' योजना शुरू की गई है।

उद्देश्य — 'नई मंजिल' योजना अल्पसंख्यक समुदायों के लिए समेकित शिक्षा एवं आजीविका पहल है। योजना का उद्देश्य उन अल्पसंख्यक युवाओं को लाभ पहुँचाना है जो बीच में पढ़ाई छोड़ देते हैं या मदरसों जैसे सामुदायिक शिक्षण संस्थानों में पढ़ाई करते हैं। इसके लिए उन्हें कक्षा 8 या 10 तक औपचारिक शिक्षा और कौशल प्रशिक्षण दिया जाता है।

स्टार्ट-अप इंडिया अभियान

शुरूआत — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 16 जनवरी, 2016 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में 'स्टार्ट-अप इंडिया अभियान' की शुरूआत की।

उद्देश्य — इस योजना का मुख्य उद्देश्य उद्यमशीलता को बढ़ावा देना है जिससे देश में रोजगार के अवसर बढ़ें। इसमें तीन वर्षों तक कर वसूली पर रोक और उद्यम पूंजी निवेश पर पूंजीगत लाभ शुल्क से छूट जैसी सुविधाएँ शामिल हैं।

क्लीन स्ट्रीट फूड परियोजना

शुरूआत — 14 मार्च 2016 को क्लीन स्ट्रीट फूड अभियान का शुभारम्भ किया गया।

उद्देश्य — इस अभियान का उद्देश्य दिल्ली की सड़कों पर बिकने वाले स्ट्रीट फूड के सुरक्षा मानकों में सुधार करना है।

गंगा ग्राम योजना

4 जनवरी, 2016 को केंद्रीय जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण मंत्री उमा भारती ने उत्तर प्रदेश के हापुड़ जिले के ग्राम पुठ में 'गंगा ग्राम योजना' की शुरूआत की। यह योजना नमामी गंगे कार्यक्रम के तहत पहल है।

इस योजना के तहत गंगा तट पर स्थित 1600 गाँवों का विकास किया जाएगा। प्रथम चरण में इस योजना के तहत 200 गाँवों का चयन किया गया है। गंगा ग्राम योजना के तहत प्रत्येक चयनित गाँव पर 1 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।

नदी सूचना प्रणाली

शुरूआत — 06 जनवरी, 2016 को केन्द्रीय जहाजरानी, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली में देश की पहली नदी सूचना प्रणाली का शुभारम्भ किया।

उद्देश्य — जलमार्ग संचालकों एवं उपयोगकर्ताओं के बीच सूचनाओं के आदान-प्रदान को युक्तिसंगत बनाना है।

यह भारत में अपनी तरह की पहली नई प्रणाली है जो गंगा नदी पर राष्ट्रीय जलमार्ग-1 पर सुरक्षित एवं सटीक नौपरिवहन को सुगम बनाएगी। प्रणाली का क्रियान्वयन अंतरदेशीय जलमार्ग प्राधिकरण द्वारा किया जाएगा जो जहाजरानी मंत्रालय द्वारा प्रशासित एक वैधानिक निकाय है।

सुगम्य भारत अभियान

शुरूआत — 03 दिसम्बर, 2015 को विश्व विकलांग दिवस के अवसर पर केन्द्रीय मंत्री अरुण जेटली ने केन्द्रीय सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री थावरचंद्र गहलोत के साथ इस अभियान का शुभारम्भ किया।

उद्देश्य — इसका उद्देश्य विकलांगता से ग्रसित व्यक्तियों के लिए सार्वभौमिक पहुँच अर्जित करना है।

उदय योजना

शुरूआत — 05 नवम्बर, 2015 को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमण्डल द्वारा

'उज्जवल डिस्कॉम एश्योरेंस योजना' (उदय) को स्वीकृति प्रदान की गई। उदय योजना केन्द्रीय विद्युत मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत एक नई योजना है।

उद्देश्य — उदय योजना का लक्ष्य बिजली विद्युत वितरण कम्पनियों का वित्तीय सुधार और उनका पुनरुद्धार करना है।

प्रौद्योगिकी अधिग्रहण एवं विकास कोष

शुरूआत — 18 नवम्बर, 2015।

उद्देश्य — इसका उद्देश्य सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों द्वारा स्वच्छ, हरित एवं कम ऊर्जा खपत वाली प्रौद्योगिकी के अधिग्रहण को सुविधाजनक बनाना है।

स्मार्ट सिटी मिशन, अटल मिशन, शहरी आवास मिशन

शुरूआत — प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 जून, 2015 को 4 लाख करोड़ रुपये की लागत वाली शहरी भारत के कायाकल्प की तीन बड़ी योजनाओं की शुरूआत की। इनमें 100 शहरों की स्मार्ट सिटी परियोजना, 500 शहरों में कायाकल्प और शहरी रूपांतरण की अटल मिशन योजना (अमरुत) एवं शहरी आवास मिशन (पीएमएवाई-प्रधानमंत्री आवास योजना) यानी 2022 तक सबको आवास योजना शामिल हैं।

स्मार्ट सिटी मिशन

स्मार्ट सिटी मिशन का उद्देश्य शहरों के बाहरी, सामाजिक, आर्थिक और संस्थागत बुनियादी ढाँचे की समूची पर्यावरण व्यवस्था का विकास करना है। इसका उद्देश्य सभी वर्गों के जीवन स्तर में सुधार और आर्थिक विकास करना है।

अमरुत योजना

अमरुत योजना के अंतर्गत शहर के प्रत्येक परिवार को नल का पानी और सीवरज कनेक्शन जैसी बुनियादी सुविधाएँ प्रदान करने के साथ-साथ ठोस कचरा प्रबंधन, सड़कों और सार्वजनिक परिवहन पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। शहरी शासन को बेहतर बनाने के लिए शहरी सुधारों को बढ़ावा दिया जाएगा।

प्रधानमंत्री आवास योजना

शहरी आवास मिशन (प्रधानमंत्री आवास योजना) आवास योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और शहरी इलाकों में निम्न आय वर्ग वाले लोगों के लिए 2022 तक 2 करोड़ मकान बनाने की योजना है।

अटल पेंशन योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 9 मई, 2015 को कोलकाता में अटल पेंशन योजना (एपीवाई) और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना (पीएमजेजेबीवाई) तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना की विधिवत शुरूआत की। देश में एक साथ इन योजनाओं की शुरूआत की गई है।

अटल पेंशन योजना (एपीवाई)

इसके अंतर्गत अंशदाताओं को 60 वर्ष की आयु पूरी होने पर 1000 रुपये से लेकर 5000 रुपये तक प्रतिमाह पेंशन मिलेगी, जो उनके अंशदान पर निर्भर करेगी। यह अंशदान किसी व्यक्ति के योजना में शामिल होने के समय उसकी आयु के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना

इसके अंतर्गत अंशदाताओं को 330 रुपये वार्षिक प्रीमियम का भुगतान करने पर 2,00,000 रुपये के जीवन बीमा का लाभ मिलेगा। प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना 18 से 50 वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी, जिनका कोई बैंक खाता

होगा जिसमें से स्वतः डेबिट सुविधा के जरिए प्रीमियम वसूल किया जाएगा।

प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना

इसके अंतर्गत दुर्घटना में मृत्यु और पूर्ण विकलांगता की स्थिति में 2 लाख रुपये और आंशिक विकलांगता की स्थिति में 1 लाख रुपये के बीमा लाभ का प्रावधान किया गया है। यह योजना 18 से 70 वर्ष की आयु समूह के उन लोगों के लिए उपलब्ध होगी जिनका कोई बैंक खाता होगा जिसमें से स्वतः डेबिट सुविधा के जरिए प्रीमियम वसूल किया जाएगा। प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना के तहत 12 रुपये वार्षिक प्रीमियम पर 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा मिलेगा।

प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना

केंद्र सरकार ने 02 जुलाई, 2015 को एक नई योजना प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना (पीएमकेएसवाई) को मंजूरी दे दी है। इसमें पाँच वर्षों (2015-16 से 2019-20) के लिए 50 हजार करोड़ रुपये की राशि का प्रावधान किया गया है तथा मौजूदा वित्तीय वर्ष के लिए 5300 करोड़ आवंटित किए गए हैं। विदित हो कि देश में कुल 14.2 करोड़ हेक्टेयर कृषि योग्य भूमि में से 65 प्रतिशत में सिंचाई सुविधा नहीं है।

इस योजना के मुख्य उद्देश्यों में सिंचाई में निवेश में एकरूपता लाना, हर खेत को मिले पानी के तहत कृषि योग्य क्षेत्र का विस्तार करना, खेतों में ही जल को इस्तेमाल करने की दक्षता को बढ़ाना ताकि पानी के अपव्यय को कम किया जा सके, सही सिंचाई और पानी को बचाने की तकनीक को अपनाना (हर बूंद अधिक फसल) आदि शामिल हैं। इसके अलावा इसके जरिए सिंचाई में निवेश को आकर्षित करने का भी प्रयास किया जाएगा।

प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना

केंद्र सरकार ने 17 सितम्बर, 2015 को प्रधानमंत्री खनिज क्षेत्र कल्याण योजना (पीएमकेकेकेवाई) शुरू की है। यह एक नया कार्यक्रम है, जिसका उद्देश्य खनन से संबंधित परिचालनों से प्रभावित लोगों तथा क्षेत्रों का कल्याण करना है। पीएमकेकेकेवाई से खनन क्षेत्र में रहने वाले प्रभावित लोगों के जीवन में आने वाली कठिनाइयाँ कम होगी।

खनन से प्रभावित क्षेत्रों में विभिन्न विकास तथा कल्याणकारी परियोजनाओं/कार्यक्रमों को लागू करना, जो राज्य और केंद्र सरकार की वर्तमान में चल रही योजनाओं/परियोजनाओं के सम्पूरक होंगे। खनन वाले जिलों में लोगों के स्वास्थ्य और सामाजिक-अर्थव्यवस्था, पर्यावरण पर खनन के दौरान और बाद में पड़े प्रतिकूल प्रभाव को कम करना/दूर करना। खनन क्षेत्रों में प्रभावित लोगों के लिए दीर्घावधि टिकाऊ जीवन यापन सुनिश्चित करना। जीवन की गुणवत्ता में ठोस सुधार सुनिश्चित करते हुए जीवन के सभी पहलुओं को शामिल करना।

समेकित बिजली विकास योजना

18 सितम्बर, 2015 को वाराणसी में प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी द्वारा समेकित बिजली विकास योजना का शुभारम्भ किया गया।

राष्ट्रीय ग्रीन इंडिया मिशन

20 फरवरी, 2014 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल की आर्थिक कार्य समिति द्वारा केन्द्र प्रायोजित के रूप में इस मिशन को मंजूरी प्रदान की गई।

संशोधित स्वर्ण मौद्रीकरण योजना

05 नवम्बर, 2015 को प्रधानमंत्री ने नई स्वर्ण मौद्रीकरण योजना की शुरूआत की।

पटवारी (मुख्य) परीक्षा, स्कूल व्याख्याता एवं आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण

सरकारी योजनाएँ

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 8 अप्रैल, 2015 को नई दिल्ली में प्रधानमंत्री मुद्रा (माइक्रो यूनिट्स डेवलपमेंट एंड रिफाइनंस एजेंसी) योजना शुरूआत की।

‘मुद्रा’ का मुख्य उत्पाद प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के तत्वावधान में सूक्ष्म व्यवसायों एवं इकाइयों को ऋण देने के लिए पुनर्वितीयकरण होगा। इसके दायरे के तहत आने वाले प्रारंभिक उत्पादों एवं योजनाओं का पहले ही सृजन किया जा चुका है और वृद्धि/विकास के चरणों तथा लाभार्थी सूक्ष्म इकाई तथा उद्यम तथा वित्त पोषण के लिए एवं उद्यमी की आकांक्षा के अनुरूप क्रमिक विकास के अगले चरण को सूचित करने के लिए एक संदर्भ बिन्दु उपलब्ध कराने के रूप में योजनाओं के नाम शिशु, किशोर और तरुण रखे गए हैं।

- शिशु : 50,000 रुपये तक का ऋण शामिल।
- किशोर : 50,000 रुपये से अधिक तथा 5 लाख रुपये तक का ऋण शामिल।
- तरुण : 5 लाख रुपये से अधिक तथा 10 लाख रुपये तक का ऋण शामिल।

सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड योजना

शुरूआत — 09 सितम्बर, 2015 को केन्द्रीय मंत्रिमण्डल ने सार्वभौमिक स्वर्ण बॉण्ड योजना को मंजूरी प्रदान की।

उद्देश्य — एसजीबी नकद भुगतान पर जारी किए जाएंगे और ग्राम आधारित सोने के वजन के अनुरूप होगा। भारत सरकार की तरफ से भारतीय रिजर्व बैंक बांड जारी करेगा। बांड की सार्वभौमिक गारंटी होगी। जारी करने वाली एजेंसी वितरण खर्च और बिक्री कमीशन बिचौलिए चैनलों को देगी जिसे भारत सरकार पुनर्भुगतान करेगी। बांड की बिक्री केवल भारत में रहने वाले नागरिकों को की जाएगी। बांड की अधिकतम सीमा एक समुचित स्तर पर रखी जाएगी जो प्रति व्यक्ति, प्रतिवर्ष 500 ग्राम से अधिक नहीं होगी।

हरित बंदरगाह परियोजना

19 जनवरी, 2016 को भारत के प्रमुख बंदरगाहों को स्वच्छ एवं हरियाली युक्त बनाने हेतु पोत परिवहन मंत्रालय द्वारा परियोजना हरित बंदरगाह का शुभारम्भ किया गया।

इस परियोजना के तहत दो कार्य क्षेत्र शामिल होंगे—पर्यावरणीय मुद्दों से जुड़ी ‘हरित बंदरगाह पहल’ और ‘स्वच्छ भारत अभियान’।

डिजिटल इंडिया कार्यक्रम

शुरूआत — प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 1 जुलाई, 2015 को डिजिटल इंडिया सप्ताह के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम की विधिवत शुरूआत की।

‘डिजिटल इंडिया कार्यक्रम’ के तीन मुख्य घटक हैं—डिजिटल अवसंरचना का निर्माण करना, सेवाओं को डिजिटल रूप में प्रदान करना और डिजिटल साक्षरता में वृद्धि करना।

उद्देश्य — उपरोक्त विजन के साथ डिजिटल इंडिया कार्यक्रम का उद्देश्य ब्रॉडबैंड हाईवे, मोबाइल जुड़ाव के लिए वैश्विक पहुँच, सार्वजनिक इंटरनेट पहुँच कार्यक्रम, ई-शासन: प्रौद्योगिकी के माध्यम से सरकार में सुधार, ई-क्रांति सेवाओं की इलेक्ट्रॉनिक आपूर्ति की जानकारी, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण: लक्ष्य शून्य आयात, रोजगार के लिए सूचना प्रौद्योगिकी कार्यक्रम उपलब्ध कराने का है।

अनेक परियोजनाएँ/उत्पाद या तो पहले ही लांच किए जा चुके हैं या लांच किए जाने के लिए तैयार हैं।

‘मेक इन इंडिया’ पहल

शुरूआत — प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने 25 सितम्बर, 2014 में भारत के निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मेक इन इंडिया पहल की शुरूआत की।

उद्देश्य — इसका उद्देश्य घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है। विदेशी प्रत्यक्ष निवेश (एफडीआई) के लिए रक्षा, निर्माण एवं रेलवे जैसे अन्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों को खोलना है।

प्रधानमंत्री उज्ज्वल योजना

शुरूआत — प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 01 मई, 2016 को उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में बीपीएल परिवारों की महिलाओं को निःशुल्क एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने वाली प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना (PMUY) का शुभारम्भ किया।

उद्देश्य — इस योजना के अन्तर्गत बीपीएल परिवारों को 5 करोड़ एलपीजी कनेक्शन प्रदान करने के लिए 8000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। बीपीएल परिवारों को प्रत्येक एलपीजी कनेक्शन के लिए 1600 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। योजना का कार्यान्वयन वित्तीय वर्ष 2016-17, 2017-18 और 2018-19 में किया जाएगा।

प्रधानमंत्री जन-धन योजना

शुरूआत — प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 28 अगस्त, 2014 को राष्ट्रीय राजधानी में औपचारिक रूप से प्रधानमंत्री जन धन योजना की शुरूआत की। इस मेगा योजना के शुभारंभ के अवसर पर सार्वजनिक बैंकों की विभिन्न शाखाओं ने उसी दिन ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में 60 हजार से भी अधिक शिविरों का आयोजन किया और अनुमानतः लगभग 1 करोड़ खाते खोले गए।

उद्देश्य — यह योजना वित्तीय समावेशन पर एक राष्ट्रीय मिशन है, जिसका उद्देश्य देश में सभी परिवारों को बैंकिंग सुविधाएँ उपलब्ध कराना और हर परिवार का एक बैंक खाता खोलना है। योजना के तहत वित्तीय साक्षरता को प्राथमिकता दी गई है। इस योजना के प्रति जागरूकता के लिए देशी भाषाओं में मानक वित्तीय साक्षरता सामग्री भी तैयार की गई है। इस योजना के तहत कम-से-कम एक खाते के साथ 7.5 करोड़ परिवारों को कवर किए जाने का अनुमान है।

स्वच्छ भारत अभियान

शुरूआत — स्वच्छ भारत अभियान केंद्र सरकार का एक राष्ट्रीय अभियान है। इस अभियान की घोषणा भारत के प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 2 अक्टूबर, 2014 को की। यह अभियान शहरी क्षेत्रों में केन्द्रीय शहरी विकास मंत्रालय और ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रीय पेयजल एवं स्वच्छता मंत्रालय द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है। अभियान की अवधि 2 अक्टूबर 2019 है।

उद्देश्य — इसका उद्देश्य खुले में शौच का उन्मूलन, मैला ढोने की प्रथा का उन्मूलन, आधुनिक और वैज्ञानिक ठोस अपशिष्ट प्रबंधन और सार्वजनिक स्वास्थ्य के साथ साफ-सफाई के बारे में जागरूकता है।

सांसद आदर्श ग्राम योजना

शुरूआत — प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 11 अक्टूबर, 2014 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में सांसद आदर्श ग्राम योजना की शुरूआत की।

उद्देश्य — गाँवों में रहने वाले लोगों को उन्नत बुनियादी सुविधाएँ और बेहतर अवसर मुहैया कराना, जिससे वे अपना भाग्य खुद बनाने में समर्थ हों। सांसद आदर्श ग्राम योजना परियोजना के तहत प्रत्येक सांसद को एक गाँव गोद लेना है और उस गाँव को 2016 तक आदर्श गाँव के रूप में विकसित करना है। इसके बाद पाँच ऐसे आदर्श गाँवों (हर साल एक गाँव) का चयन किया जाएगा और उनके विकास के काम को वर्ष 2024 तक पूरा किया जाएगा।

दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रीमंडल की बैठक में 20 नवम्बर, 2014 को देश भर के ग्रामीण परिवारों तक बिजली की पहुँच प्रदान करने के लिए दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (डीडीयूजीजेवाई) को प्रारंभ करने को अनुमति दी गई।

उद्देश्य — इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि और गैर-कृषि उपभोक्ताओं को विवेकपूर्ण तरीके से विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करना सुलभ बनाने के लिए कृषि और गैर-कृषि फीडर सुविधाओं को अलग-अलग किया जाएगा। इसके साथ ही ग्रामीण क्षेत्रों में वितरण और उप-पारेषण प्रणाली को मजबूत किया जाएगा जिसमें वितरण ट्रांसफॉर्मर, फीडर और उपभोक्ताओं के लिए मीटर लगाना सम्मिलित होगा।

राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना

मृदा परीक्षण के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 19 फरवरी, 2015 को राजस्थान में श्रीगंगानगर जिले के सूरतगढ़ से राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड (एनएसएचसी) योजना की शुरूआत की। इस योजना के तहत केंद्र सरकार अगले तीन वर्षों में देश के 14 करोड़ किसानों को ‘राष्ट्रीय मृदा स्वास्थ्य कार्ड’ उपलब्ध कराएगी। इस योजना के तहत किसान अपनी खेती की जमीन की मिट्टी की जाँच करा सकेंगे। अधिक यूरिया, अधिक पानी और अधिक उर्वरकों के प्रयोग से मिट्टी की गुणवत्ता प्रभावित होती है। इसके माध्यम से किसानों को फसल के हिसाब से उर्वरकों का उपयोग करने की सुविधा भी मिलेगी। यह कार्ड मृदा परीक्षण के बाद जारी किया जाएगा। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य उर्वरकों के अनियंत्रित प्रयोग को रोकना है। इसके अनुरूप खेती करने पर किसानों को तीन एकड़ जमीन पर वर्ष में 50 हजार रुपये तक की बचत हो सकती है।

प्रधानमंत्री रोजगार योजना

प्रधानमंत्री रोजगार योजना का उद्देश्य — प्रधानमंत्री रोजगार योजना के तहत लोन दिए जाने की इस योजना का उद्देश्य युवाओं को रोजगारोन्मुख बनाना है। इस योजना से युवाओं को मोटी ब्याज दर से मुक्ति और बैंकों की मार्फत सस्ते ब्याज दर पर लोन अथवा ऋण उपलब्ध करवाना है। इसका एक उद्देश्य यह भी है कि युवा नौकरीयों पर निर्भर न रहकर स्वरोजगार के लिए कार्य करें।

शिक्षा सूत्र एजेन्सी

आपके शहर या गाँव में
शिक्षा सूत्र अखबार की एजेन्सी
लेने के लिए सम्पर्क करें
7665050402, 9982745862

स्वत्वाधिकारी स्वामी, प्रकाशक एवं मुद्रक आनन्द शर्मा के लिए नोवा प्रिन्टर्स, 5, बागर गली, हाथीपोल, उदयपुर से मुद्रित एवं कार्यालय — 226, पीपली वाली गली, गणेश नगर, पहाड़ा, उदयपुर से हिन्दी व अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित। सम्पादक : कमलकिशोर,

Reg. No. : RAJBIL/2014/58602, Postal Regd. No : RJ/UD/29-129/2015-2017 कार्यालय फोन न. — 0294-2470402, 9982745862, ईमेल — info@shikshasutra.com